

नम्बर  
अहका  
हुक्म  
में

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी—श्री देवी सिंह (R.A.S)

दावा संख्या

1/17

दायर दिनांक

06.02.2024

निर्णय दिनांक

14.08.2024

### उनवान

सुनीता देवी पुत्री री हरिकिशन मीना पत्नि श्री कमलेश जाति मीना आयु करीब 44 साल निवासी ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर

— वादी

### बनाम

1. हरिकिशन पुत्र दोला जाति मीना आयु करीब 75 साल
2. रमेश चन्द पुत्र हरिकिशन जाति मीना आयु करीब 35 साल निवासीयान रसीला परसादी का बास ग्राम दुब्बी तहसील राजगढ जिला अलवर
3. लाडबाई पुत्री हरिकिशन पत्नि महेश चन्द जाति मीना आयु करीब 40 साल निवासी ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर
4. पूजा पुत्री हरिकिशन पत्नि रामस्वरूप जाति मीना आयु करीब 30 साल निवासी मीना नंगला गंज खेडली जिला अलवर
5. तहसीलदार साहब कम सब रजिस्टार साहब मालाखेडा (अलवर)

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188,

राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति:—

1. श्री देवेन्द्र प्रधान वकील वादी
2. श्री पीसी मीना वकील प्रतिवादीगण

### निर्णय

कील वादी ने वाद पेश किया। वाद के विचाराधीन रहते हुये प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत किया कि प्रार्थनी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध विवादित आराजीयात मे हिस्सा प्राप्त तु वाद पेश किया है। वादनी जाति से मीणा है और प्रतिवादीगण भी जाति से मीणा है। मीणा जाति र रूढी नीति व सामाजिक रीति रिवाज लागू होते है। मीणा समुदाय मे सम्पत्ति मे पुत्री को अधिकार प्रदान नही किये हुये है। वादनी का विवाह प्रतिवादीगण द्वारा लगभग 25-26 साल पूर्व बडी मुमधाम से किया गया था। जिस विवाह मे प्रतिवादीगण द्वारा अपनी हैसियत से बढकर दान दहेज देया गया था। तथा समय समय पर वादनी की रूपये पैसे से मदद करते है व आज भी करते चले आ रहे है। इसके अतिरिक्त हम प्रतिवादीगण ने सामाजिक रीति रिवाज व भारतीय संस्कृति अनुसार वादनी के बच्चो के भौत पेज भरे है। वादनी विवादित आराजी के किसी भी अंश व हिस्सा पर कभी काबिज नही रही है। वादनी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 मीणा जाति है। तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के प्रावधान मीणा जाति पर लागू नही होते है। मीणा जाति मे महिलाओ को सम्पत्ति मे अधिकार प्राप्त नही होते है। मीणा जाति मे बेटी की शादी हो जाने पर हिन्दु अविभाजित

उपखण्ड अधिकारी  
मालाखेड़ा (अलवर)

वार (एचयूएफ) का भी हिस्सा नहीं माना जाता है। वाद विधि द्वारा वर्जित है इसलिये वादनी का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर वादनी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब नहीं देते हुये सीधे ही पेश करने का कथन किया। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने जो दावा पेश किया वो स.स. 88, 188 में पेश किया है। ऑर्डर 7 रूल्स 11 का विन्दु सं० 2 को पढा जिसमें वादी प्रतिवादी पुत्री है। जिसकी शादी हो चुकी है। और 25 या 30 साल शादी हुये हो चुके है। ऑर्डर 7 रूल्स विन्दु सं० 3 पर हिन्दु विधि लागू नहीं होती है। जिसके संबंध में कानून पेश कर दुंगा। मीणा जाति की लडकिया जो होती है जब तक अविवाहित होती है तब तक उन्हें उत्तराधिकार मिलता है। शादी के बाद पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिलता वादी के पिता की वाद में वर्णित आराजी की खरीदी हुई है। वादी जीवित है। मैं मेरी भूमि को किसी को भी दे सकता हूँ। यदि मैं मर जाऊँ तो आप हिस्सा मांगती भाईयो से लेकिन मेरे जीवित रहते आपको कोई हक नहीं बनता है। वाद विधि विरुद्ध है। दावा चलने योग्य नहीं है। वाद खारिज किया जावे।

रिवीटल प्रतिवादी का कथन है कि इनका अब कब्जा नहीं है। दावे के विन्दु सं० 3 अवलोकन करे। विन्दु सं० 4 व 5 का अवलोकन करे। आप के कथन व बहस विरोधाभासी है। जो रूलिंग पेश की है विरासत का जो इन्तकाल खुलता है उसमें पुत्रियों को हिस्सा नहीं मिलता आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पिता के मर जाने पर मिलता तो मैं अभी जीवित हूँ ऑर्डर रूल्स 11 किस आधार पर लगाई है मेरे प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल्स 11 के विन्दु सं० 3 को देखे। वाद विधि द्वारा वर्जित है। सैक्शन लिखा जाना आवश्यक नहीं है। प्रतिवादी सं० 3 मेरी पुत्री है। वो हिस्सा नहीं लाई मेरी तीन पुत्रिया है। मेरा ऑर्डर 7 रूल्स 11 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी ने वाद की भूमि को वादी के पिता की स्वयं पैतृक सम्पत्ति बताया है। जबकि ये सम्पत्ति स्वयं अर्जित नहीं है। उनको उनके पिता से मिली है। पिता का दादाजी की भूमि थी। यदि दादाजी जीवित होते तो यह जमीन हमें मिल जाती और हमारे नाम आती। हमारे पति सरकारी सर्विस करते थे। पहले हम यहाँ थे तो हमारे हिस्से को जोतते बोते वाद में बम्बई चले गये। अब भूमि इनके कब्जे में है। हमारी शादी में इन्होंने कोई दान दहेज नहीं किया है। इसलिये हमें मुकदमा लाना पडा। यदि तुम्हारी खरीद की जमीन होती तो अधिकार लागू होते। ये पैतृक भूमि है। पत्रावली का अवलोकन कर सकते है। जमाबन्दी देखे। इसमें कई अधिकारी है। यदि उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता तो यह जमीन किसी को भी नहीं मिलती। श्री वाई बनाम पानवाई नजीर में देखे। पिता की खरीद की भूमि थी। इसलिये दावा खारिज किया गया है। मीरा बनाम गणेश 1966 आरआरडी पेज 71 इस पर लागू नहीं होती है। ये इसलिये लागू नहीं होती है क्योंकि ये जमीन दो उत्तराधिकारियों में पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है। इनके ऑर्डर रूल्स 11 का अवलोकन करे। ऑर्डर 7 रूल्स 11 में सबक्लॉज का अंकन नहीं किया। इनकी प्रेरण देखे। इनका प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने अपने पिता की विवादित आराजी में से अपना 1/5 हिस्से का अनुतोष चाहा गया है। वकील प्रतिवादी द्वारा कथन किया है कि मीणा जाति में विवाहिता पुत्री का किसी प्रकार का हिस्सा नहीं मिलता है। वकील प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2011 (2) आर.आर.टी 765 बोर्ड ऑफ

  
उपखण्ड अधिकारी  
मालाखंडा (अलवर)

मेन्सु फॉर राजस्थान अजमेर बउनवान वाद भौरी व अन्य बनाम जगदीश व अन्य रिवीजन एलआर नंबर 3359/जयपुर ऑफ 2008 निर्णय 17 मार्च 2011 पेश किया। जिसमे माननीय न्यायालय ने तैपादित किया है कि **Under Section 2 of Hindu Succession Act, After Re-married Widow Have No right in the property of former husband and married daughter has also no right in ancestral land of the father** प्रस्तुत वाद पूर्णतः चर्या होती है। इसी प्रकार आर.आर.डी सितम्बर 2006 पेज 580 मूलचन्द बनाम मंगली व य मे प्रतिपादित किया है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान मीणा जाति के वेत्तयो पर लागू नहीं होते हैं। क्योंकि इन प्रावधानों को मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागू करने के ध मे राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उपरोक्त चन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं होने पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत है।


अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं होने पर खारिज किया जाता है

  
देवी सिंह

(R.A.S)

उपसखण्ड अधिकारी  
मालाखेड़ा (अलवर)

आज दिनांक 14.08.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।


  
देवी सिंह

(R.A.S)

उपसखण्ड अधिकारी  
मालाखेड़ा (अलवर)

संशोधन :- दिनांक 2-9-2024 →

निर्णय दिनांक 14-8-2024 में उनवान मे प्रतिवादी सं. 2 का नाम सुरेश चन्ह पुत्र हरिश्चिान के स्थान पर सुरेश चन्ह पुत्र हरिश्चिान पठा जावे /

  
उपसखण्ड अधिकारी  
मालाखेड़ा (अलवर)